International Journal of Social Research and Development
www.socialsciencejournal.net
Online ISSN: 2664-8709, Print ISSN: 2664-8695
Received: 19-01-2025, Accepted: 20-02-2025, Published: 08-03-2025
Volume 7, Issue 1, 2025, Page No. 47-48

भारत में जाति की राजनीति – एक अध्ययन

निर्मल बम्बोरिया
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, श्री सांवरियाँ जी राजकीय महाविद्यालय, मण्डफिया, चित्तौड़गढ़, राजस्थान, भारत

सारांश
भारत में औपनिवेशिक दौर में और उसके बाद के शुरूआती दशकों में जाति को आधार बनाकर परिवर्तनकारी राजनीति करने की कोशिशे हुई। डॉ. अम्बेडकर ने दलितों में राजनीतिक चेतना भरने की पुरजोर कोशिश की। संविधान द्वारा भारत में जाति, निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, व्यवस्था कायम की गई है, परन्तु हमारी राजव्यवस्था के सम्मुख प्रमुख चुनौति जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, सम्प्रदायवाद आज भी विद्यमान है। हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ परन्तु आज भी हमारे राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो जातिवाद से प्रभावित न हो। उक्त शोध पत्र में भारतीय लोकतन्त्र में जातिगत राजनीति का अध्ययन किया गया है।

मुल शब्दः औपनिवेशिक, दलित, धर्म निरपेक्ष, क्षेत्रवाद, भाषावाद, सम्प्रदायवाद, जातिवाद, भारतीय लोकतन्त्र, राजव्यवस्था।

जाति की लोकतान्त्रिक राजनीति में भूमिका की महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि इसने जाति को सामाजिक सम्बन्धों के परिवेश से निकालकर प्रतियोगी राजनीति का अभिन्न अंग बना दिया।

रॉबर्ट हार्डग्रेव के अनुसार

''जाति भारतीय समाज व आर्थिक जगत का एक आधारभूत पक्ष है, भारतीय राजनीति पूर्णतः इसी पर आधारित है।[१] कुछ समाजशास्त्रियों का मानना है कि'' जाति नई भूमिका अदा कर रही है, जिसमें वह सबसे ज्यादा प्रभाव राजनीति पर डाल रही है। इसके अन्तर्गत अनेक जातीय संगठन दबाव समूह के रूप में कार्य करते है जैसे – हिन्दू महासभा, जाट महासभा, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा, अखिल भारतीय यादव महासभा, अखिल भारतीय वैश्य महासभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा आदि। ये जातीय संगठन केवल एक जाति से सम्बन्धित होते हैं तथा उसी जाति के हितों का संरक्षण करते है।

जातिप्रथा की शुरुआत

जातिप्रथा की शुरूआत वैदिककाल में हुई जिसके अनुसार चार वर्ण है ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र। सामान्यतः जाति व्यवस्था अपने मौलिक रूप में उपयोगी थी। यह श्रम विभाजन व कार्यकुशलता पर आधारित थी। प्रारम्भ में जाति व्यवस्था कर्म पर आधारित थी जो बाद में विकृत होकर जन्म पर आधारित हो गयी। जाति प्रथा में बाद में कठोरता आती गई और एक जाति से दूसरी जाति में अंतः क्रिया असंभव हो गयी जाति व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ –

- भारत में जाति ऐसे समुदाय है, जिनका अपना विकसित जीवन है और इसकी सदस्यता जन्म से ही निश्चित होती है।
- भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति जानता है और जातियों के पद सोपान में ब्राह्मण सबसे उपर माना जाता है।
- जातियों के आधार पर खान–पान और सामाजिक आदान–प्रदान में अन्तराल था.
- गाँव तथा शहर में जाति के आधार पर पृथकता की भावना बनी रहती है।
- कुछ जातियाँ कतिपय विशेष प्रकार के व्यवसायों को अपना पुश्तैनी अधिकार समझती है।
- जातियों की परिधि में वैवाहिक आदान–प्रदान होता है।
- जातियाँ कई उपजातियों में बटी हुई होती है।
- उपजातियों में भी वैवाहिक सीमाएं है।

परम्परावादी भारतीय समाज में आधुनिक राजनीतिक संस्थाओ से एवं राजनीतिक आधुनिकीकरण से यह विचार किया गया था कि जाति संस्था समाप्त हो जायेगी। परन्तु वयस्क मताधिकार के कारण जाति राजनीति शक्ति के रूप में उभरी है।

राजनीति में जातिवाद का अर्थ

राजनीति में जातिवाद का अर्थ है जाति का राजनीतिकरण अर्थात जाति को अपने दायरे में खीचकर राजनीति उससे अपने काम में लाने का प्रयास करती है। दूसरी ओर जाति को भी देश की व्यवस्था में भाग लेने का मौका मिलता है। नेता सत्ता प्राप्ति हेतु जाति का उपयोग करते है। जाति के रूप में उन्हें एक संगठन मिल जाता है।

जाति का राजनैतिक स्वरूप–

हमारे देश के राजनीतिज्ञ एक अजीब असमंजस्य की स्थिति में है जहां एक ओर जातिगत भेदभाव मिटाने की बात की जाती है, वहीं दूसरी ओर जाति के आधार पर वोट बटोरने की कला में निपुणता हासिल करना चाहते है। भारतीय समाज की सबसे विशिष्ट एवं प्रमुख विशेषता जातीय सामाजिक स्तरीकरण है। भारत में स्तरीकरण के आधार को जाति व्यवस्था के नाम से जाना जाता है जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं–

- लोकतन्त्र में जाति के प्रभाव का अध्ययन करना ।
- लोकतन्त्र में जाति की भूमिका का अध्ययन करना।
- जाति और राजनीति के संबन्ध पर अध्ययन करना। जाति और मतदान व्यवहार का विश्लेषण करना।
- जाति के सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण को समझना।

जाति और राजनीति पर प्रमुख विचार

रजनी कोठारी

जातीय नेतृत्व द्वारा जातीय हितों या मुद्दों को उठाकर जाति में अपना समर्थन बढ़ाकर राजनीतिक लाभ उठाना ही वास्तविक जातिगत राजनीति है।

अतः राजनीति में जातिवाद के प्रभाव को श्जातिगत राजनीतिश कहा जाता है। इसके अन्तर्गत क्षेत्र विशेष में कोई जाति विशेष राजनीतिक रूप से ज्यादा प्रभावशाली एवं शक्तिशाली होती हैं ।

जातिगत राजनीति के प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव

1. सामाजिकता एवं एकता भी भावना का विकास हुआ है।
2. जाति की राजनीति में लोगों में राजनीतिक सक्रियता पैदा की है।
3. सक्रियता से उन जातियों का महत्व बढ़ा जो पहले राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक रूप से शक्ति विहीन थे ऐसी जातियों में भी राजनीतिक जागरूकता आई ।

नकारात्मक प्रभाव

1. जातिगत राजनीति से बन्धुत्व एवं एकता की भावना को हानि पहुँचती है।
2. स्वयं के हितों के संघर्ष के कारण वैमनस्यता पैदा होती है।
3. समाज के वातावरण में अशान्ति पैदा होना।
4. जातिगत आधार पर मतदान करने से योग्य व्यक्ति चुनाव हार जाते है। जो समाज व देश के लिए घातक है।
5. राष्ट्रीय हितो के बजाय जाति हितों का प्राथमिकता देना।
6. राजनीतिक दलों का निर्माण जाति आधार पर होना ।
7. जातिवादी सोच रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती हैं जिसमे वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता।
8. अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में असुरक्षा की भावना का विकास होता है।
9. जातिवाद लोकतान्त्रिक भावना के विरुद्ध होता है ।
10. वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा मिलता है।

राजनीति में जाति की भूमिका का मुल्यांकन

राजनीतिक दलों ने जब जनता को सम्मोहित करने में अपने आप को असमर्थ महसूस किया, तब राजनीति का खेल खेलने के लिए नेताओं ने राजनीति में जातिवाद का सहारा लिया। जातिवाद के कारण जहां राज्य का उदेश्य जनकल्याण का था उसको बदलकर रख दिया उसका वास्तविक उद्देश्य विभिन्न जातियों को संतुष्ट करना मात्र रह गया।

अतः राजनीति में समाज व्यवस्था के दोषों को बढ़ावा देते हुए उसे परस्पर जाति संघर्ष एवं वैनमस्यता की आग में डाल दिया। जिस पर राजनेता अपने हाथ सेंकते रहे है। जातिवाद ने लोकतन्त्र की भावना के विरुद्ध कार्य किया है। अब आवश्यकता इस बात की है कि जाति के नकारात्मक स्वरूप के स्थान पर सकारात्मक स्वरूप की स्थापनी की जाय।

निष्कर्ष

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव कैंसर एवं एड्स जैसे भयंकर रोगों की तरह सर्वत्र फैल गया है जिसका निदान असंभव सा प्रतीत होता है भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का मूल्याकन करना अत्यंत जटिल कार्य है।

अतः जातिवाद देश, समाज और राजनीति के लिए बाधक है, लोकतन्त्र व्यक्ति को ईकाई मानता है न की किसी जाति या समूह को। जाति और समूह के आतंक से मुक्त रखना ही लोकतन्त्र का आग्रह है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. राजकिशोर (संपा) – जाति प्रथा का विकास, आज के प्रश्न जाति का जहर, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2004 पृ. 15–16
2. आहुजा राम – भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत प्रकाशन, जयपुर 1995 प्र. स. 202
3. चौबे कमल नयन– जातियो का राजनीतिकरण, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली 2008 पृ. 34.
4. कोठारी रजनी – कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ओरिर्य लॉंगमन, नई दिल्ली – 1970.
5. सिंह योगेन्द्र – भारतीय परम्परा का आधुनिकीकरण, थॉमस प्रेस, नई दिल्ली – 1973
6. सर देसाई राजदीप – 2014 का चुनाव जिसने भारत को बदल दिया, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली – 2015
7. राय प्रणय – भारतीय जनादेश : चुनावों का विश्लेषण, – 2019
8. शर्मा डी. आर – भारतीय शासन एवं राजनीति, रावत प्रकाशन जयपुर 2023
9. गुर्जर रविन्द्र डॉ. गायत्री – भारतीय लोकतन्त्र में जाति की राजनीति प्रभाव एवं भूमिका – 2024